मई 2023

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

समाजवादी ही कर रहे मुकाबला

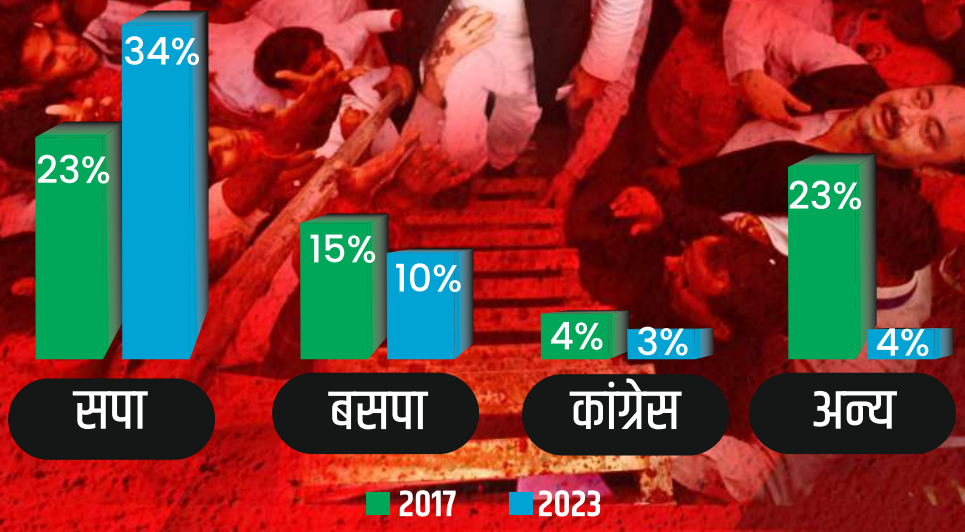

निकाय चुनाव : सपा को मिले मत प्रतिशत में पहले से काफी ज्यादा इजाफा

R.N.I. No. 68832/97

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला दो पार्टियों सपा और भाजपा के बीच है। इसके अलावा अन्य कोई दल नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी और भाजपा मुकाबले में हैं। आगे भी ऐसा ही होगा और सपा ही भाजपा को परास्त करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हर चुनावी लड़ाई के लिए तैयार रहें।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन

मई 2023
वर्ष 24| संख्या 07

प्रिय पाठकों

आप सभी के प्यार, उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन से आपकी प्रिय पत्रिका समाजवादी बुलेटिन, बदली हुई साज-सज्जा के साथ अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। हम आपके आभारी हैं कि अभी तक के सफर में हम आपकी कसौटी पर खरे उतर सके हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृपया अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।

धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

समाजवाद की प्रासंगिकता 04

06 कवर स्टोरी

समाजवादी ही कर रहे मुकाबला

राष्ट्रीय फलक पर छा रहे अखिलेश 31

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिली है। भाजपा की हार के बाद राष्ट्रीय राजनीति में यह बात मजबूती से चल पड़ी है कि भाजपा को परास्त करने के लिए विपक्षी एका की जरूरत है। क्षेत्रीय क्षत्रपों को आगे करने की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की हिमायत को कर्नाटक के नतीजों ने बल दिया है।

अखिलेश सरकार के कामकाज से ब्रिटिश हाईकमीशन प्रभावित 40

2024 की लड़ाई में कर्नाटक के सबक 28

समाजवाद की प्रासंगिकता

उदय प्रताप सिंह

डॉ राममनोहर लोहिया अपने रचनात्मक विरोध के लिए देशभर में जाने जाते थे। गांधीवादी और पंडित नेहरू के अभिन्न मित्र होने के बावजूद उन्होंने नेहरू की नीतियों का समय समय पर घोर विरोध किया। 1962 में उन्होंने नेहरू के विरुद्ध लोकसभा का चुनाव लड़ा और हारे। बाद में अपने साथियों का अनुरोध स्वीकार करते हुए फर्रुखाबाद से उप चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे।

लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के प्रमुख वक्ता डॉ. राममनोहर लोहिया थे। 90 मिनट तक डॉ. लोहिया संसद में धारा प्रवाह हिन्दी में बोलते रहे। उनकी बात का शीर्षक था– तीन आना बनाम तीन रूपये। लोहिया ने कहा– मेरे प्यारे प्रधानमंत्री नेहरूजी के राज में आम जनता तीन आना से कम पर ही गुजर करती है। प्रधानमंत्री के कुत्ते का खर्च तीन रूपये रोज का है। तत्कालीन मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पंडित नेहरू को एक पर्चा दिया जिसमें लिखा था– तीन आना नहीं पंद्रह आना।

पंडित नेहरू ने अध्यक्ष की अनुमति से हस्तक्षेप करते हुए कहा– राममनोहर, यह तीन आना नहीं पंद्रह आना है। पंडित जी को संसदीय शिष्टाचार याद आ गया। उन्होंने अपने आपको संभालते हुए कहा– माननीय सदस्य, आम आदमी की उपलब्धि तीन आना नहीं पंद्रह आना है। लोहिया जी ने स्पीकर की अनुमति प्राप्त कर हस्तक्षेप करते हुए पंडित नेहरू से कहा– पंडित जी आपके राममनोहर संबोधन से मेरा दिल पुरानी यादें ला रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी आलोचना करता जा रहा हूँ, आप मुझे वही स्नेह देते जा रहे हैं जो स्वराज से पहले देते थे। डॉक्टर लोहिया ने आंकड़े बताते हुए कहा– पंडित जी, नंदा जी को उनके अफसर भरमा रहे हैं। आंकड़ा तीन आना ही है पंद्रह आना

फाइल फोटो

नहीं। मैं नंदा जी से उनके दफ्तर में मिल कर सफाई दूंगा। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज में संपादकीय छपा। उन्होंने हिंदी में ऐसे संसदीय भाषण की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा कि हिंदुस्तानी भाषाओं में भी ओज है।

लोकसभा में लोहिया की तीन आना बनाम पंद्रह आना बहस बहुत चर्चित रही। उस समय उन्होंने 18 करोड़ आबादी के चार आने पर जिंदगी काटने तथा प्रधानमंत्री पर 25 हजार रुपए प्रतिदिन खर्च करने का आरोप लगाया। देश आज भी लोहिया की शुद्ध संसदीय बहस का कायल है। विपक्ष ही नहीं तत्कालीन सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी लोहिया के तर्कपूर्ण भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

वर्ष 1960 के दशक में ही डॉ. लोहिया ने देश की भावी समस्याओं को बखूबी समझ लिया था। इसीलिए वह कहा करते थे– गरीबी हटाओ, दाम बांधो, हिमालय बचाओ, अंग्रेजी हटाओ, नदियां साफ करो, पिछड़ों को विशेष अवसर दो, बेटियों की शिक्षा व विकास का समुचित प्रबंध हो, गरीबों के इलाज का इंतजाम हो, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले, खेती और उद्योग में समन्वय बनाकर विकास का एजेंडा तय हो, गरीबी के पाताल और अमीरी के आकाश का फासला कम करने के जतन हों। लोहिया के उठाये मुद्दे आज भी प्रासंगिक और ज्वलंत हैं।

देश की राजनीति आज भी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। लोहिया का शरीर जरूर शांत हुआ मगर उनकी आत्मा आज भी जिन्दा है। उनके विचार आज भी जन जन के प्रेरणास्रोत हैं। तब विपक्ष के नेताओं का प्रधानमंत्री भी आदर करते थे। आज सरकारों को विपक्ष दुश्मन लगता है, यही लोकतंत्र के क्षरण का मूलभूत कारण है।

बुलेटिन ब्यूरो

मजबूत इरादों, अवाम का भरपूर समर्थन और डटकर मुकाबला करने की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कूवत ने निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के दांत खट्टे कर दिए। एक बार फिर यह साफ हो गया कि यूपी में भाजपा को रोकने का माद्दा सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है। निकाय चुनाव में जिस तरह दूसरे दल तीसरे और चौथे नम्बर के लिए लड़े, वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा से डटकर मुकाबला करते हुए यह संदेश दे दिया कि यूपी में वही भाजपा को रोकने की ताकत रखती है।

अंकों के खेल में जीतने के लिए भाजपा ने जतन तो बहुत किए मगर अवाम के सभी वर्गों ने उसकी कोशिशों और रफ्तार पर समाजवादी पार्टी के जरिये ब्रेक लगा दिया। नगर निगमों में जीत का ढिंढोरा पीट रही सत्ताधारी भाजपा यह बताने से गुरेज कर रही है कि वह इसी यूपी की 108 नगरपालिका परिषद व 353 नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बुरी तरह हारी। उसे यह बताने भी हिचक है कि जहां वह जीती है, वहां समाजवादी पार्टी से उसे कड़ी टक्कर मिली। भाजपा को यह भी बताने में शर्म आ रही है कि तमाम मंत्रियों, सांसदों के इलाकों में वह, समाजवादी पार्टी से बुरी तरह पस्त हुई।

शहर से गांव-गिरांव तक समाजवादी पार्टी का बढ़ा वोट प्रतिशत भी गवाही दे रहा है कि 2024 में समाजवादी

समाजवादी ही कर रहे मुकाबला

पार्टी ही भाजपा को रोक पाएगी।

यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव हुए। पूरब में 4 मई और पश्चिमी इलाकों में 11 मई को मतदान हुआ। चुनाव प्रचार शुरू होते ही सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी डटकर खड़ी हो गई। निकाय चुनाव शुरू हुआ तो देवरिया से सहारनपुर तक एक ही माहौल था-सपा बनाम भाजपा। चुनाव नजदीक आते-आते यह माहौल और गाढ़ा होता गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के रोड शो में जनसैलाब उमड़ने लगा। पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आ गई कि समाजवादियों ने भाजपा से डटकर मुकाबला किया। निकाय चुनाव के नतीजे गवाही देने लगे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीधा मुकाबला भाजपा से होने जा रहा है। तिकड़म से आंकड़ों में भाजपा भले ही अंकों में ज्यादा दिखती हो पर जमीनी हकीकत यही है कि आमजन ने समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद किया। समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत इसका सबूत है।

नगर पालिका परिषद के चुनाव में ही समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। 2017 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को जहां 23 प्रतिशत वोट मिले थे, 2023 के चुनाव में उसने 34 प्रतिशत वोट पाकर दूसरे दलों को पीछे छोड़ दिया और भाजपा से लड़ने वालों में सबसे आगे रही। बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में महज 10 प्रतिशत ही वोट मिले जबकि पिछले चुनाव में उसने 15 प्रतिशत वोट हासिल किए थे।

कांग्रेस भी इस चुनाव में कहीं खड़ी नजर नहीं आई। उसने भी चुनाव में एक प्रतिशत वोटों का नुकसान उठाना

मंत्रियों-सांसदों के गढ़ में पस्त हुई भाजपा

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा सिर्फ जीत का शोर मचा रही है और यह बात छुपाए हुए है कि अवाम के गुस्से का उसने कितना नुकसान उठाया है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों के प्रति असंवेदनशीलता के नतीजे में उसे दो दर्जन से ज्यादा मंत्रियों व अपने 25 सांसदों के इलाकों में कैसे हार मिली है, इसपर भाजपा चर्चा करने से बच रही है।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी अपने गृह जनपद महराजगंज में दोनों

नगर पालिका अध्यक्ष का पद भाजपा को नहीं जिता पाए। आठ नगर पंचायतों में सिर्फ 3 ही भाजपा जीत सकी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर जिले की आठ नगर पंचायतों में एक भी भाजपा नहीं जीत सकी। एक नगर पालिका भी हार गई क्योंकि सपा-रोलोद गठबंधन डटकर खड़ा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी नगर पालिका परिषद व चार नगर पंचायतों पर भाजपा को हार मिली। मंत्री नंदगोपाल नंदी तो प्रयागराज में अपना ही बूथ हार गए।

भाजपा के करीब 25 ऐसे सांसद हैं जिनके इलाकों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। इसमें आजमगढ़ के निरहुआ, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के इलाके की हापुड़ नगरपालिका, खलीलाबाद के सांसद प्रवीण निषाद के क्षेत्र में खलीलाबाद व मगहर में भाजपा को हार नसीब हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सांसद बेटे राजबीर सिंह के एटा में पांच नगर पंचायत, सांसद सत्यपाल सिंह के क्षेत्र बागपत की सभी छह नगर पंचायतों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। फायर ब्रांड सांसद साक्षी महराज, सांसद रमाशंकर सिंह कठेरिया के इटावा ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा को शर्मनाक हार मिली पर हार को बताने के बजाए, जीत-जीत चिल्लाने में लगी है ताकि उसकी नाकामी, जनता का गुस्सा और तमाम मोर्चों पर उसकी विफलता ढंकी-छिपी रहे।

पड़ा। इस बार उसे सिर्फ 3 प्रतिशत ही वोट मिले जबकि पिछले चुनाव में उसने 4 प्रतिशत वोट पाए थे। भाजपा से मुकाबला करने में इस बार निर्दलीय व अन्य दल भी कहीं खड़े नजर नहीं आए। पिछले चुनाव में अन्य जिसमें निर्दलीय भी शुमार किए जाते हैं, को 23 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि इस बार वे सिमट कर 4 प्रतिशत पर आ गए। ये वोट प्रतिशत यह बताने के लिए काफी हैं कि भाजपा से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही डटकर लड़ी। सत्ताधारी भाजपा और सरकारी तंत्र से लड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी की नगर पालिका अध्यक्ष की 35 सीटें व सभासद की 425 सीटें हासिल कीं। यह भी कह सकते हैं कि ये सीटें उसने अवाम के बूते लड़कर सत्ताधारी भाजपा से छीनीं हैं।

नगर पंचायतों के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में अच्छी वृद्धि हुई । आंकड़े बता रहे हैं कि नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 34 प्रतिशत वोट मिले जबकि पिछले 2017 के चुनाव में उसे 19 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में महज 9 प्रतिशत वोट ही हासिल हो पाए। अन्य दलों का वोट प्रतिशत भी गिरा और उन्हें सिर्फ 11 प्रतिशत ही वोट हासिल हो सके जबकि पिछले चुनाव में ये 44 प्रतिशत तक वोट पा चुके थे।

समाजवादी पार्टी ने 79 नगर पंचायत अध्यक्ष और 485 वार्ड सदस्य के पदों पर चुनाव जीतकर सत्ताधारी दल को रोकने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं गठबंधन के दूसरे दल यानि राष्ट्रीय लोकदल ने भी नगर निगमों में 10 पार्षद, 7 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 7 नगर पंचायत अध्यक्ष, 40 सभासद के पदों पर जीत दर्ज कराई। यूपी के नगर निगमों में भी समाजवादी पार्टी ने 191 पार्षद जीतकर भाजपा के सामने विपक्ष की मजबूत लकीर खींची।

तिकड़म, सरकारी मशीनरी और दूसरे जतन से भाजपा ने अंकों में भले ही जीत दर्ज की हो पर जमीनी हकीकत यही है कि अवाम के सभी वर्गों में समाजवादी पार्टी ने एक अलग मुकाम बना लिया है। अवाम का यह नजरिया समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का शुभ संकेत भी कहा जा सकता है

नगर निगमों में भी समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले कड़ी टक्कर दी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 मेयर सीट पर भाजपा से मुकाबला किया था जबकि इस बार शहरी मतदाताओं के बूते समाजवादी पार्टी ने भाजपा को 9 शहरों में कड़ी टक्कर देते हुए उसके पसीने छुड़ा दिए। जिन शहरों में समाजवादी पार्टी ने कड़ा मुकाबला किया उनमें लखनऊ, गोरखपुर, फिरोजाबाद, बरेली, अयोध्या, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर शामिल है। इन शहरों में सपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे।

कई शहरों में तो सपा का कड़ा मुकाबला देखकर भाजपा को जीत के लिए दूसरे कई तरह के हर्बा-हथियार का भी इस्तेमाल करना पड़ा। गोरखपुर इसकी मजबूत मिसाल है जहां पड़े वोटों से एक लाख ज्यादा वोट गिन दिए गए। बाद में इसे गिनती की त्रुटि बताकर भाजपा प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया गया।

तिकड़म, सरकारी मशीनरी और दूसरे जतन से भाजपा ने अंकों में भले ही जीत दर्ज की हो पर जमीनी हकीकत यही है कि अवाम के सभी वर्गों में समाजवादी पार्टी ने एक अलग मुकाम बना लिया है। अवाम का यह नजरिया समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का शुभ संकेत भी कहा जा सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में समाज के सभी तबके ने भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी को बेहतर माना। पसंद किया।

भाजपा से डटकर लड़े समाजवादी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की तारीफ की है कि उन्होंने सत्ताबल, धनबल, तिकड़म, अधिकारियों के संरक्षण के बाद भी भाजपा से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंड़े अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह हारी है। चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बेहतर आते अगर भाजपा सरकार ने छलकपट, सत्ताबल और धनबल का दुरुपयोग करते हुए धांधली न की होती। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भाजपा ने नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार ने लड़ा। यह पूरी तरह से सरकार के प्रबंधन का चुनाव था। भाजपा के पक्ष में नतीजों के लिए हर तरह के षड्यंत्र किए गए।

निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दिया है। बड़ी संख्या में अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता बन कर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने निकाय चुनाव की मतदाता सूची से लेकर मतगणना तक में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी और बेवर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सीडीओ व अन्य अधिकारियों ने चुनाव नतीजे बदलने की कोशिश की जिससे जनता में गुस्सा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब हारने लगती है तो कुछ दलों को आगे करके लड़ाई लड़ती है। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद आया आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। बावजूद इसके संगठन की ताकत से समाजवादी पार्टी का नगर पंचायतों और नगर पालिका में प्रदर्शन 2017 के मुकाबले काफी शानदार रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित किया

फिर भी समाजवादी पार्टी और अन्य ने मिलकर समेकित रूप से भाजपा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनावों में लगातार बेईमानी कर रही है। जब जनता आवाज उठाती है तो सरकार पुलिस को आगे कर देती है। झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में जीते समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों व भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि भाजपा ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची से वोट कटवाने से लेकर, फर्जी वोट डलवाए, मतगणना धीमी कराई। शासन प्रशासन ने भाजपा एजेंट के तौर पर काम किया और समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में भाजपा ने निकाय चुनाव में जमकर धांधली की। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान देखकर बौखलाई भाजपा ने वोटरों को धमकाने, वोट देने से रोकने के लिए पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि शासन-प्रशासन व चुनाव आयोग इस धांधली को देखते हुए भी मूकदर्शक की भूमिका निभाते रहे।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को सामान्य सुविधाएं देने से वंचित रखा इसलिए जनता में भाजपा के प्रति भारी आक्रोश है। निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का मन बनाए मतदाताओं ने जमकर पक्ष में वोटिंग की। इससे बौखलाहट में भाजपा ने असामाजिक तत्वों के सहयोग से हर जगह भय और आतंक का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

उन्होंने कहा कि सत्ता की भूखी भाजपा येनकेन प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस खुद मतदाताओं को वोट डालने से रोकती रही। सत्तापक्ष द्वारा गांव-मोहल्लों में पुलिस लगाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया। सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के छानबे उपचुनाव में भी सत्ता पक्ष ने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया।

सत्ता संरक्षित वोटों की लूट

बुलेटिन ब्यूरो

UP Tak

Up Nikay
की घटनाएं

BY यूपी तक MAY 11, 2023

UP Nikay Chunav Result:
धांधली, सपाइयों का हंगामा, पुलि
लाठियां

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 14

हिन्दुस्त

पुलिस का घेरा तोड़
घुसी और पेटियों में

हाल-ए-बिल्हौर

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कानपुर नगर जिले में बाकी जगहों पर तो मतदान शांतिपूर्वक हो गया पर बिल्हौर नगर पालिका के तीन बूथों पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया।

इन बूथों के पीठासीन अधिकारियों के मुताबिक शाम 5:30 बजे अचानक 25-30 लोगों के समूह बूथ नंबर 16, 22 और 25 में सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए घुस आए। हंगामा किया और मतपेटियों में पानी, स्याही और अपने साथ लाया गया तेजाब उड़ेल दिया। इससे हंगामा मच गया और मतदाता बूथ से डर कर भाग गए। निर्वाचनकर्मी सहम कर किनारे खड़े हो गए। बवाली समूह नारेबाजी

■ भीड़ ने विधायक के
■ पुनर्मतदान के लिए

बिल्हौर में गुरुवार को भाजपा

लखनऊ से मंगाए

दोबारा मतदान कराने की अनु
आयोग की सरकारी प्रिंटिंग प्रे
लखनऊ से मतपत्र छपकर आ
की व्यवस्था कराने के लिए बि
की मुनादी कराई गई। रात में
गल्ला मंडी से रवाना की गई।

होम वीडियो राजनीति क्राइम अपना यूपी फोटो गैलरी शॉर्ट्स शिक्षा

Chunav Live: अलीगढ़-नोएडा में फर्जी वोटिंग
, बागपत में ASP ने लांघी मर्यादा

LESS THAN A MINUTE 294 VIEWS

पूर्वांचल के सभी छह जिलों में नाम गायब होने की शिकायतें, कानपुर में भी हजारों वोटिंग से वंचित

लिस्ट में गड़बड़ी से कई लोग वोट से वंचित

दूसरा चरण

कानपुर में विधायक के पूरे परिवार का नाम गायब

मैनपुरी में मतगणना में
स ने अंधेरे में भांजी

May 2023 03:51 PM IST

इंडिया टीवी | वीडियो | आईपीएल 2023 | भारत | विदेश | मनोरंजन | खेल | पैसा | राशिफल | धर्म | हेल्थ | LIVE TV

YOU ARE AT: Hindi News › उत्तर प्रदेश › सीतापुर में निकाय चुनाव से पहले भारी बवाल, जमकर हुई मारपीट, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

सीतापुर में निकाय चुनाव से पहले भारी बवाल, जमकर हुई मारपीट, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

पुलिस पर किए गए पथराव में एक पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हुआ। घटना की सूचना पाकर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजीं।

Reported By : Dharmendra Kumar Mishra Edited By : Malaika Imam

paper
ान

ड़ बूथों में भीड़
डाला तेजाब

समर्थकों पर आरोप लगा की नारेबाजी
लखनऊ में रातो-रात छपवाए मतपत्र

इयों की पुलिस से नोकझोंक हुई।

ए गए मतपत्र, कराई मुनादी
मति आने के बाद लखनऊ राज्य निर्वाचन
स से मतपत्र छपने को भेजे गए। रात में
ाए। एडीएम न्यायिक सूरज यादव को मतदान
ल्हौर भेजा गया। तीनों वार्ड में दोबारा मतदान
1:30 बजे मतदान के लिए चार पोलिंग पार्टियां

निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा ने एक बार फिर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं और जमकर धांधली की। वोटों की लूट होती रही और समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर दस्तक देती रही पर सब तरफ मौन था। धांधली रोकने की कोशिशें कहीं भी नजर नहीं आईं। मतगणना के दौरान भी वोटों की लूट की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की गई। गोरखपुर में पड़े वोटों से एक लाख अधिक वोट गिन दिए गए, समाजवादी पार्टी आवाज बुलंद करती रही मगर भाजपा प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया गया। पीलीभीत में भी यही हाल रहा। वहां के प्रत्याशी ने बाकायदा बताया कि कितने वोट पड़े और कितने गिने गए फिर भी कोई एक्शन न होना सत्ताधारी दल की मनमानी की गवाही दे गया।

निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को मतदान हुआ। मतदान के दिन तमाम जिलों से धांधली, वोटों की लूट की खबरें आईं तो समाजवादी पार्टी ने

चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। समाजवादी पार्टी ने बूथवार शिकायतें दर्ज कराईं कि किस बूथ पर किस तरह मनमानी, धांधली की जा रही है। आयोग में लिखित शिकायतें की गईं मगर पहले की तरह ही सिर्फ आश्वासन मिला पर कार्यवाही कोई नहीं हुई।

समाजवादी पार्टी ने 4 मई को निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मैनपुरी जनपद की नगर पंचायत कुसमरा के बूथ संख्या 2,6,7,8,9 एवं वार्ड संख्या 9 के बूथ संख्या 309 में भाजपा जिलाध्यक्ष ने बूथ के अंदर घुसकर पोलिंग को कैप्चर कर लिया है। नगर पंचायत घिरोर पर भाजपा नेता फर्जी आधार कार्ड से बाहरी लोगों का वोट डलवा रहे हैं। नगर पंचायत भोगांव में सत्तापक्ष के इशारे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती नसरीन बानो के पति अकबर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आयोग को समाजवादी पार्टी ने बताया कि गोरखपुर के वार्ड संख्या 39 के बूथ संख्या 181, 600 पर पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची और मतदाताओं को बीएलओ द्वारा दी गई मतदाता पर्ची में काफी अंतर है। हर बूथ पर लगभग 100-100 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

मुरादाबाद के बारे में बताया गया कि प्रिंस रोड अंसार इंटर कालेज के बाहर अधिकारियों द्वारा आईडी चेक करने के नाम पर मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे ही वाराणसी, फिरोजाबाद व गाजीपुर जनपदों के बारे में तथ्यों के साथ शिकायत की गई मगर कोई कार्यवाही होते नहीं दिखी।

मतदाता सूची में गड़बड़ी के साथ मतदान केन्द्रों में भी अनपेक्षित बदलाव किए गए। इससे हजारों की संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह गए। दूसरे चरण में भी सत्ताधारी दल की मनमानी, धांधली, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की शिकायतें आम रहीं

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी ने मतदान के एक दिन पहले 10 मई को पत्र भेजकर बताया कि नगर निकाय चुनावों के दूसरे चरण के मतदान में सत्तापक्ष मतदान बाधित करने, मतदाताओं को डराने-धमकाने और फर्जी मतदान करने की साजिशें की जाएंगी। दूसरे दिन मतदान के दौरान ये आशंका सही साबित हुईं।

निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल की मनमानी, धांधली रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण में धांधली रोकने के लिए फिर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन सौंपकर 11 मई 2023 को प्रदेश के 38 जनपदों में स्थानीय निकायों के चुनावों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान को सुनिश्चित करने की मांग की।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने पत्र में लिखा है कि निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 37 जनपदों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी के साथ मतदान केन्द्रों में भी अनपेक्षित बदलाव किए गए। इससे हजारों की संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह गए। उन्होंने 11 मई को सभी 38 जनपदों में किसी भी किस्म की धांधली रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की पर दूसरे चरण में भी सत्ताधारी दल की मनमानी, धांधली, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की शिकायतें आम रहीं।

निकाय चुनाव के साथ ही रामपुर

जनपद के विधानसभा क्षेत्र-34 स्वार और मिर्जापुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र-395 छानबे में हो रहे उपचुनाव के दौरान भी सत्तापक्ष द्वारा मतदाताओं को डराने-धमकाने तथा बूथ कैप्चर करने की शिकायतें करते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई। इन विधानसभा उपचुनावों में सत्तापक्ष की मनमानी जगजाहिर हुई और यहां भी वोटों की जमकर लूट की गई। मनमानी और धांधली की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इससे पहले 6 मई को चुनाव आयोग को पत्र भेजकर समाजवादी पार्टी ने जनपद मिर्जापुर के विधानसभा क्षेत्र-395 छानबे के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री आशीष पटेल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर, प्रधानों को सत्तापक्ष के प्रत्याशी को वोट करने और कराने के लिए धमकाकर आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने की शिकायत की और कार्यवाही की मांग की।

समाजवादी पार्टी ने पत्र में शिकायत की कि मंत्री का यह आचरण उनके द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सम्मानित प्रधानों को धमकाने जैसा कृत्य सरासर आचार संहिता का उल्लंघन व स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाला और लोकतंत्र की हत्या करना है। समाजवादी पार्टी ने मांग की कि इसका तत्काल संज्ञान लेकर मंत्री श्री आशीष पटेल के विरूद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर कठोर कार्यवाही की जाए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।

शहरों में भी एक शक्ति है समाजवादी पार्टी

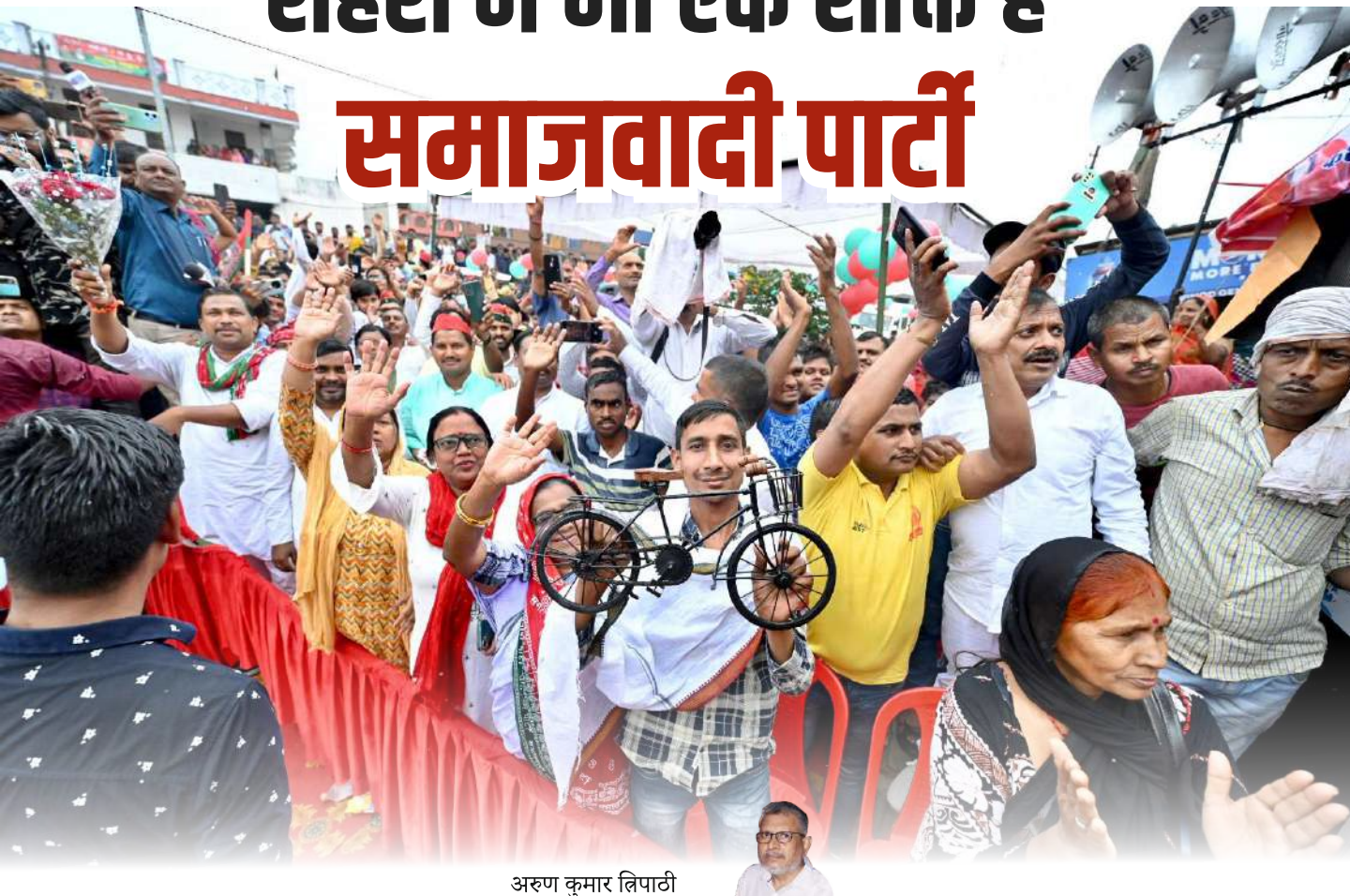

अरुण कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

आमतौर पर उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव सत्तारूढ़ दल के ही माने जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो हर हाल में अपनी जीत का इंतजाम करती ही है। इसलिए पिछली बार की तरह इस बार भी अगर नगर निगम की सभी 17 सीटों पर उसने कब्जा कर लिया तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चूंकि शहर सवर्णों और संपन्न लोगों के गढ़ हैं इसलिए उनका रुझान स्पष्ट रूप से हिंदूवादी और दक्षिणपंथी भाजपा की ओर रहता ही है। वे व्यवस्था से सवाल नहीं करते बल्कि सदैव उसके साथ चलते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इसी को कुछ भाजपा के खैरख्वाह विश्लेषक ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं।

लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत और सरकार व सरकारी तंत्र के माध्यम से जीते जाने वाले इन चुनावों में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सीना तानकर खड़ी दिखी। 17 में से 9 नगर निगमों में समाजवादी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में भाजपा के अलावा अगर किसी पार्टी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल हुआ है तो वह है समाजवादी पार्टी। सन 2017 में नगर पंचायत के चुनावों में भाजपा को 23 प्रतिशत वोट मिले थे

तो इस बार यानी 2023 में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 38 प्रतिशत हो गए लेकिन अपने वोटों के विस्तार में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। 15 प्रतिशत बढोत्तरी के साथ सपा के 19 प्रतिशत वोट बढ़कर 34 प्रतिशत हो गए जबकि बसपा के वोट पांच प्रतिशत घटे हैं।

इसी तरह नगर पालिका परिषद में अगर भाजपा का वोट 14 प्रतिशत बढ़ा है तो सपा का वोट भी 11 प्रतिशत बढ़ा। समाजवादी पार्टी को 2017 में 23 प्रतिशत वोट मिला था जो इस साल 34 प्रतिशत हो गया। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों की जीत में भी समाजवादी पार्टी को उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। नगर पालिका परिषद के कुल 199 अध्यक्षों में अगर 88 अध्यक्ष भाजपा के जीते हैं तो 35 अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के विजयी हुए हैं जबकि बसपा के 15 और कांग्रेस के 4 जीते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के कुल 544 पदों में अगर भाजपा ने 198 पर कब्जा किया तो सपा ने 78 पद हासिल किए हैं।

नगर पालिका परिषद के सदस्यों के 5321 पदों में से भाजपा को 1341 तो सपा को 421 पर जीत हासिल हुई है। बसपा 189 और कांग्रेस 91 पर विजयी हुई है।

वास्तव में तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया और उनके विश्लेषकों ने न तो अपने अपने वेबसाइटों पर पूरा चुनाव परिणाम प्रस्तुत किया है और न ही कम वोट पड़ने के कारणों का विश्लेषण किया है। जब यथार्थ की स्थिति का ही सही विश्लेषण नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी के वोटों में इतने बड़े इजाफे की चर्चा की उम्मीद करना तो बेमानी है। कई भक्त विश्लेषकों का यह लिखना कि महराजगंज अमरोहा और कुशीनगर में प्रयागराज, गोरखपुर और अयोध्या से ज्यादा वोट पड़े इस तथ्य को छुपाने का तरीका है कि 13 नगर निगमों में 2017 के मुकाबले कम वोट पड़े।

वास्तव में भाजपा का भक्त मतदाता भी अब उसकी विकास नीति से उदास है इसीलिए 13 नगर निगमों में सिर्फ 47.89 प्रतिशत वोट पड़े जो कि पिछली बार के मुकाबले 2 प्रतिशत

UJJWAL LAKSHAY ASSOCIATES
समाजवादी पार्टी

अखिलेश यादव जिंदाबाद

कम ही थे। अयोध्या नगर निगम में भले ही भाजपा उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के आशीष पांडे को हराकर जीत गए लेकिन यह एक हकीकत है कि रामपथ पर लोग वोट डालने नहीं निकले। वैसी ही स्थिति प्रयागराज और गोरखपुर में भी अन्यान्य कारणों से देखी गई।

उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दो स्थिति है। या तो लोग भयभीत हैं या फिर मीडिया के एकतरफा प्रचार से सम्मोहित। इसलिए भाजपा की जीत को लोकतांत्रिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी बताने से पहले समाजवादी पार्टी के बढ़ते वोट प्रतिशत पर गौर करना ही होगा। पुलिस राज और बुलडोजर राज से जनता त्रस्त है और वह अपना विरोध किसी न किसी रूप में दर्ज करना चाहती है।

उसके सामने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल दिखता नहीं। इसीलिए जनता ने शहरों के प्रतिनिधित्व के लिए भी गांवों में असर रखने वाली समाजवादी पार्टी को चुना न कि कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी शहरों की पार्टी नहीं रही है। कई बार सत्ता में रहने के बाद उसके समर्थक जरूर बने हैं लेकिन जिस अनुपात में शहरों में भाजपा और संघ समर्थक हैं और रोज शाखा के माध्यम से उन्हें जिस बड़े पैमाने पर हिंदुत्व की कट्टरता की घुट्टी पिलाई जाती है उस माहौल में अगर उन इलाकों में समाजवादी पार्टी अपनी जगह बना रही है तो यह उसकी विचारधारा और नेतृत्व का ही कमाल है।

समाजवादी पार्टी को शहरों में जो वोट मिलते हैं वे उस तबके के हैं जो पिछले 30-40 सालों में गांवों से उठकर वहां जाकर बसे हैं। या वे लोग जो शहर के बड़े लोगों के घरों में काम करते हैं या रेहड़ी पटरी पर व्यापार करते हैं। अगर भाजपा के समर्थक उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखते हैं जो शहर की परिधि पर रहते हैं और रोजाना दूर से चल कर उनके घरों में काम करने आते हैं तो शहर के सामान्य घरों में बसने

वाले लोग भी उनके अन्याय के प्रति एक जज्बा रखते हैं।

शहर का विस्तार समाजवादियों के सहारे ही होता है। भले उसके केंद्र में पूंजीवाद हो। यह मंडल का प्रभाव है कि मध्य और पिछड़ी दलित जातियों का मध्यवर्ग शहरों में बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों की आबादी भले शहर के भीतरी इलाकों में हो लेकिन किसी भी पार्टी को जिताने के लिए किसी एक तबके का वोट काफी नहीं होता है। समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोट यह बताते हैं कि शहर के भीतर कितने तरह के अन्याय हैं और कितनी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे बिना रह जाती हैं।

यह वोट एक प्रतिरोध हैं बेवजह की तोड़फोड़ के विरुद्ध, अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई के विरुद्ध और शहर के आधुनिक जीवन में मौजूद जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध। यह वोट उस सपने का नाम है जो बराबरी के लिए देखा गया है। यह वोट उस अमन चैन का नाम है जो विभिन्न धर्मों के बीच कायम होना लाजिमी है। यह वोट उस संविधान की रक्षा के लिए पड़ा है जिस पर आज सबसे ज्यादा खतरा है।

जहां समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों में इजाफा करके यह बता दिया है कि वह एक मजबूत विपक्षी दल के तौर पर अपनी उपस्थिति कायम रखे हुए है वहीं कांग्रेस और बसपा जैसे दलों को यह सोचना चाहिए कि वे सपा का दामन थाम कर आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ करामात कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि नगर निकायों के चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव में उसी तरह से प्रतिफलित हों जिस प्रकार वे दिख रहे हैं लेकिन उनकी पूरी तरह उपेक्षा भी नहीं की जा सकती।

यह वोट उस सपने का नाम है जो बराबरी के लिए देखा गया है। यह वोट उस अमन चैन का नाम है जो विभिन्न धर्मों के बीच कायम होना लाजिमी है। यह वोट उस संविधान की रक्षा के लिए पड़ा है जिस पर आज सबसे ज्यादा खतरा है

यह बात गौर करने लायक है कि समाजवादी पार्टी के यह वोट किसी झटके में नहीं बढ़ रहे हैं। वे लगातार बढ़ रहे हैं। विधानसभा के 2022 के चुनाव में उसके वोटों में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तो इस चुनाव में नगर पंचायत में 15 तो नगर पालिका परिषद में 1 1 प्रतिशत बढ़े हैं। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के वोट प्रतिशत में इतनी तीव्र बढ़ोतरी कोई सामान्य बात नहीं है। 2017 में सपा को 21.82 प्रतिशत वोट के साथ 47 सीटें मिली थीं तो इस बार 32.06 प्रतिशत वोट के साथ 111 सीटें मिली हैं।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह परिणाम उत्साह बढ़ाने वाला तो है लेकिन और मेहनत करने की प्रेरणा देने वाला भी है। यही वह उर्वर जमीन है जिस पर खड़े होकर वह 2024 में लोकतंत्र को बचाने और संघवाद की रक्षा करने की लड़ाई लड़ सकती है। यह वोट प्रतिशत बढ़ें और सीटें बढ़ें तो देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले प्रदेश में लोकतंत्र की मशाल को जलाया जा सकता है।

समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना की मांग करके सामाजिक न्याय का बड़ा अभियान छेड़ा है। अगर 2024 में दिल्ली की सरकार बदली और जाति जनगणना शुरू हुई तो कोई वजह नहीं है कि सामाजिक न्याय की नई राजनीति शुरू होगी और सांप्रदायिकता और बुलडोजर न्याय का अंत होगा।

निकाय चुनाव

फिर दिखा समाजवादियों का संघर्ष

राजकुमार भाटी

श्रीमद्भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 47 में श्रीकृष्ण कहते हैं-सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरे सामर्थ्य से प्रयास करना, परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि सत्ता से ज्यादा अवाम की तकलीफें दूर होना जरूरी है। वे समझाते थे कि कभी तख्त पर कभी तख्ते पर, इसलिए बिना घबराए जनता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए।

समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रही है और डटकर मुकाबला कर रही है। अतीत से अब तक के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि अन्याय-अत्याचार, दलितों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वह समाजवादी पार्टी ही है। अवाम भी जानती है कि उसकी तकलीफों

को दूर कराने के लिए समाजवादियों के संघर्ष का कोई सानी नहीं है।

यही वजह है कि निकाय चुनाव में जनता के सभी वर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी पार्टी के वोटों में बड़ा इजाफा हुआ। जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सपा की मुकाबला करने की ताकत का संकेत भी मिल गया। जनता के समर्थन के बूते समाजवादी साथी जनता के सवालों पर सत्ताधारी भाजपा से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अवाम की तकलीफें दूर कराने के लिए मुकाबला करना, संघर्ष करना ही समाजवादी साथियों की पूंजी है।

समाजवादी पार्टी नेताजी के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रही है। 80 के दशक में नेताजी-मुलायम सिंह यादव ने देश-प्रदेश को बताया कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। नेताजी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और अवाम की तकलीफों को दूर करना अपनी प्राथमिकताओं में रखा। सत्ता की परवाह किए बिना वह डटे रहे, लड़ते रहे बिना परिणाम की सोचे, संघर्ष ही उनका नारा था। समाजवादियों को संघर्ष विरासत में मिला और वे उसी राह पर डटे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की स्पष्ट नीतियां अवाम को भी समझ में आ गईं हैं इसलिए वे भी समाजवादी पार्टी से जुड़ती जा रही है। यह शुभ संकेत है कि समाजवादियों के संघर्ष को समाज का हर तबका पसंद कर रहा है और यह जान चुका है कि उसकी तकलीफें दूर करने में यही समाजवादी साथी मुकाबला कर रहे हैं। लिहाजा निकाय चुनाव के नतीजे भी बता रहे हैं कि सपा ही मुकाबले में है। सत्ताधारी भाजपा के छल, प्रपंच, बाहुबल, धनबल, प्रशासनिक तंत्र के साथ होने के बाद भी जनता का रुझान देख लीजिए।

निकाय के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक मीडिया द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे इस चुनाव में भाजपा ने कोई बहुत बडी विजय प्राप्त की हो। जबकि वास्तविकता इससे एकदम भिन्न है, भाजपा सरकार ने इस चुनाव मे जिस कदर धांधली, बेइमानी, मशीनरी का दुरूपयोग और (धन) बल, बाहुबल व अनैतिक साधनों का प्रयोग किया उसे देखते हुए उसे प्राप्त सीटें और मत कुछ भी नही है। सत्तारूढ़ दल की मनमानी के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उसने फिर एक बार साबित किया है कि भाजपा से मुकाबले का दम सिर्फ उसमें ही है।

निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिद्ध

YOUTH
ICON
AKHILESH

कर दिया है कि वह प्रतिबद्ध और बहादुर कार्यकर्ताओं और मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सरकारी मशीनरी, पुलिस, माफिया तंत्र, काला धन और तमाम संसाधन थे और समाजवादी पार्टी केवल कार्यकर्ताओं और अपने नेता अखिलेश यादव की लोकप्रियता के दम पर लड़ रही थी।

सरकारी मशीनरी ने तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया। सपा समर्थक वोट भारी संख्या में काटे गये। प्रत्याशियों को तरह-तरह से डराया-धमकाया गया और परेशान किया गया। मतदान मे बाधा उत्पन्न की गई। भाजपा के लिए फर्जी मतदान कराया गया। फिर मतगणना में धांधली की गई। कई जगह जीते हुए प्रत्याशियों को हारा घोषित कर भाजपा प्रत्याशियों को जीत के प्रमाण पत्र दे दिये। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अच्छी संख्या में सीटें हासिल कीं और 2017 के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट प्राप्त किये।

इस बार के चुनाव में सत्ता का दुरूपयोग करके भाजपा ने बेशक सभी सत्रह नगर निगमों में महापौर की सीटें जीत ली हों, किन्तु यह तथ्य भी रेखंकित करने योग्य है कि नगर निगमों में समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले 5.73 लाख वोट अधिक प्राप्त हुए है।

सपा के प्रति जनता का रुझान देखकर बौखलाई सत्ताधारी भाजपा ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा लगातार आगे चल रही थी तो प्रशासन ने मतगणना की गति धीमी कर दी और देर रात को भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया।

गोरखपुर में जितने वोट पड़े थे उससे एक लाख ज्यादा गिन दिये गये। मुगलसराय में सोनू किन्नर को करीब 800 वोट की बढत थी किन्तु प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। दबाव में प्रशासन को दुबारा मतगणना करानी पड़ी और उसमें सोनू किन्नर की विजय हुई। दादरी में मतदान के दिन सपा समर्थक बूथों पर कई बार लाठीचार्ज की जिससे सपा मतदाताओं के वोट कम पड़े।

इन सब धांधलियों के बावजूद समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। नतीजे साबित कर रहे हैं कि समाजवादी ही मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी सत्ताधारी भाजपा से मुकाबला करने की कूवत समाजवादी साथियों में ही है।

(लेखक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं)

2024 की लड़ाई में कर्नाटक के सबक

अरविन्द मोहन
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री की 19 रैलियां और आठ घंटे तक चले 26 किमी के 'ऐतिहासिक' रोड शो समेत कुल 6 रोड शो, भाजपा के धुरंधरों की 3116 रैलियां और 1377 रोड शो, 9125 जन सभाएं और 9077 नुक्कड़ सभाओं के बाद 311 मंदिरों और मठों में शीश नवाना। इतना कुछ करने के बाद भी भाजपा कर्नाटक में चुनाव हार गई।

प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के आखिरी दस दिनों में मणिपुर की हिंसा, पाकिस्तान की पल-पल बदलती तस्वीर और जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने समेत अपनी सारी जिम्मेवारियां भुलाकर चुनाव प्रचार ही किया और बजरंगबली के नारे लगवाने से लेकर ऐसे काफी सारे काम किए जो चुनाव प्रचार की सामान्य मर्यादाओं को तोड़ने वाला था-कानून से क्या गलत हुआ यह मामला संभवत: अदालत पहुंच भी गया है।

अकेले प्रधानमंत्री ही नहीं भाजपा ने 15 केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने 128 राष्ट्रीय नेताओं को कर्नाटक में कैंप कराया था। भाजपा के भारी भरकम और तामझाम से भरपूर चुनाव प्रचार के सरकारी-गैर सरकारी खर्च, पार्टी और उम्मीदवारों के खर्च, चुनाव में मतदाताओं के ऊपर किए गए खर्च को जोड़ते हुए बस इस तथ्य को याद रखें कि आज कारपोरेट डोनेशन का नब्बे फीसदी हिस्सा सिर्फ भाजपा को मिल रहा है। करीब साढ़े पांच करोड़ मतदाताओं वाले कर्नाटक का एक 'लाभ' यह रहा कि वह हिंदीभाषी नहीं है वरना आम तौर पर ऐसे चुनाव में कथित संघ परिवार के लाखों कार्यकर्त्ता चुनाव क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और चुनाव कराके ही वहां से टलते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव में तो यह संख्या लाखों में होती है।

सामान्यत: होटल में रुककर और वाहन समेत प्रचार का प्रत्येक कार्यकर्ता का औसत खर्च क्या होता है और यह खर्च कौन उठाता है, कोई भी समझ सकता है। पर कर्नाटक में भी ऐसे लाखों नहीं तो पचासों हजार स्वयंसेवक पहुंचे ही थे। चुनाव प्रचार में क्या-क्या हुआ और प्रधानमंत्री समेत भाजपा के नेता किस सीमा तक गए यह गिनवाना पहले पैरा की गिनती से भी मुश्किल है। चालीस फीसदी की सरकार नाम से कुख्यात भाजपा की बोम्मई सरकार

ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने से लेकर और कितने चुनावी फैसले किए इसकी गिनती भी मुश्किल है।

इन सबको गिनवाने का उद्देश्य अपने पाठकों के मन में खौफ पैदा करना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कर्नाटक की भाजपा की हार का बहुत बड़ा महत्व है। वह जीत कांग्रेस ने कैसे हासिल की, ऐसे विकट चुनाव अभियान को कैसे पछाड़ा और कहां से साधनों का मुकाबला किया, यह गिनवाना भी उद्देश्य नहीं है। चुनाव का विश्लेषण तो हमारा उद्देश्य नहीं ही है क्योंकि भाजपा का मत प्रतिशत 36 पर बरकरार रहना काफी दूसरी चीजें भी बताता है जो ऊपर बतायी बातों से ज्यादा डरावनी हैं।

एक समाज और देश-विरोधी विचारधारा, जीवन शैली के लिए हार में भी एक तिहाई से ज्यादा मतदाताओं का साथ होना एक 'उपलब्धि' तो है ही। अब आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यह कौन सी जमात है यह पहचान कोई अनजानी भी नहीं है।

हैरानी नहीं कि इस जीत की अनुगूंज कर्नाटक से बाहर भी सुनी गई और खुश होने वालों में कांग्रेस के साथ ही लगभग पूरा विपक्ष है। लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने खुलकर अपनी राय दी। और इस जीत के साथ कर्नाटक में कांग्रेसी सरकार बनाने के साथ ही विपक्षी एकता की बात भी उतने ही दमदार ढंग से चलने लगी। संयोग यह था कि उधर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी कर्नाटक में लगी थी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विपक्षी एकता की मुहिम में लगातार दौरे कर रहे थे। उससे भी हवा बदली और मोदी मंडली की इस पराजय ने उसे तूफ़ानी रंग दिया।

इधर कई सवालों पर नरम पड़े शरद पवार को नया जोश आता दिखा तो विपक्ष में कांग्रेस के बाद नंबर दो और तीन की ताकत रखने वाले अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने नए किस्म की हवा बनाई। अभी भी विपक्षी एकता पर अरविन्द केजरीवाल, नवीन पटनायक और चंद्रशेखर राव जैसों की राय बहुत खुलकर नहीं आई है लेकिन उन्होंने भी कर्नाटक के बदलाव को सार्थक माना।

हैरानी नहीं कि इस जीत की अनुगूंज कर्नाटक से बाहर भी सुनी गई और खुश होने वालों में कांग्रेस के साथ ही लगभग पूरा विपक्ष है। लगभग सभी विपक्षी नेताओं ने खुलकर अपनी राय दी। इस जीत के साथ कर्नाटक में कांग्रेसी सरकार बनाने के साथ ही विपक्षी एकता की बात भी उतने ही दमदार ढंग से चलने लगी

तो कर्नाटक चुनाव का 2024 के लिए और बड़ा महत्व है। जाहिर तौर पर इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के नतीजे भी हवा बनाने बिगाड़ने में मदद करेंगे। अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। पर कर्नाटक का मतलब मोदी और भाजपा को उनकी सत्ता और साधनों के साथ हराने का भरोसा मजबूत करना है।

इसका यह भी मतलब है कि भाजपा को तिकोने-चौकोने मुकाबले का लाभ न हो तो उसे हराने में आसानी रहती है। जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है, भाजपा लड़ाई के तीसरे कोण को भी अपने हक में इस्तेमाल कर लेती है- ओवैसी जैसा बनावटी तीसरा-चौथा कोण ज्यादा काम नहीं आता।

इसलिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का यह कहना सही है कि लड़ाई को सीधा रखने के लिए जिस राज्य में जो दल भाजपा के मुकाबले बड़ा है उसे नेतृत्व दिया जाए। साथ ही यह भी जोड़ना चाहिए कि जहां जो नेता हों वह दूसरों का भी ध्यान रखे। कई जगह यह स्थिति और उलझी है-बंगाल, पंजाब, केरल वगैरह में।

दूसरा सबक यह है कि भाजपा से मुकाबला हो तो गवर्नेंस के सवाल को ऊपर रखें, आइडेंटिटी के सवाल को नहीं। जाति, संप्रदाय, राष्ट्रीयता के सवाल पर भाजपा ज्यादा कुशलता से लड़ने लगी है और गवर्नेंस के सवाल पर फिसड्डी है। कर्नाटक में भाजपा शुरू से आखिर तक इसका प्रयास करती रही और कांग्रेस तथा मुसलमानों को बधाई दी जानी चाहिए कि वे इस जाल में नहीं फंसे।

आरक्षण खत्म करने के सवाल पर भी मुसलमानों ने चुनाव तक एकदम चुप्पी रखी। पहले जाति और सांप्रदायिकता एक-दूसरे के खिलाफ जाते थे। खुद को पिछड़ा बताने के साथ मोदी जी ने सरकारी खजाने से 'लाभार्थी' बनाकर जातिवाले विभाजन की आंच मद्धिम की है। भाजपा को आगे भी आधे हिन्दू मतदाताओं को संप्रदाय के नाम पर गोलबंद कराने में मुश्किल आएगी-खासकर तब जब उसके शासन का प्रदर्शन फीका हो और लोग यह हिसाब लगाते रहें।

पर कर्नाटक चुनाव ने यह बताया है कि महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित

और पिछड़े भाजपा से दूर हुए हैं। पिछले चुनावों की तुलना में इन समूहों का कम वोट भाजपा को मिला है। पहले भाजपा को दंगाई पार्टी मानकर महिलाएं उसे कुछ कम वोट देती थीं (इंदिरा गांधी के चलते कांग्रेस को कुछ ज्यादा समर्थन भी करती थीं)। इधर मोदी जी के उदय के बाद स्थिति बदली थी और भाजपा को महिलाओं का ज्यादा वोट मिल रहा था। कर्नाटक चुनाव इसे बदलता लग रहा है। भाजपा ने आरक्षण नीति में बदलाव का सर्वाधिक लाभ आदिवासियों को दिया था (क्योंकि पहले वही सबसे ज्यादा नुकसान की स्थिति में थे) लेकिन उसे सर्वाधिक नुकसान भी आदिवासी सीटों पर हुआ है।

दलितबहुल सीटों पर भी उसे काफी नुकसान हुआ है जिसमें मलिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष होना भी एक मुद्दा हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा से भी बेहतर जन कल्याण योजनाओं की घोषणा करके उसे मात दी।

इसलिए 2024 चुनाव में विपक्ष को मोदी तथा भाजपा और संघ परिवार से लड़ते हुए बहुत सारे सवालों पर सचेत होना होगा। और यह कहने में हर्ज नहीं है कि आज भी अगर विपक्षी राज्य सरकारें हैं और भाजपा को हर जगह चुनौती देने वाले नेता और दल हैं तो उन्होंने भी इन फार्मूलों को कम या ज्यादा अपनाया ही है। पर इस जीत से कुछ प्रथमिकताएं बदलने की सीख मिलती है। जाहिर तौर पर पहली सीख तो सिर्फ मोदी या भाजपा विरोध की जगह एक समानांतर नीति और कार्यक्रम की है।

इसके लिए पार्टियों का विलय तो नहीं हो सकता लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसा एक साफ-सुथरा एजेंडा देश के सामने रखना होगा। भाजपा ने कर्नाटक हारने के पहले से सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार का मसाला अपने लोगों और गोदी मीडिया के माध्यम से छेड़ दिया था। 2024 के लिए भी उनकी बड़ी रणनीति यही है कि मोदी के मुकाबले कौन के सवाल को ऊपर किया जाए। विपक्ष में भी अतिशय महत्वाकांक्षी लोग हैं और बड़ी पार्टी होने के चलते कांग्रेस का अपना दावा होगा। कांग्रेस का व्यवहार अब तक चाहे जैसा हों उसकी तरफ से अभी कोई बड़ा दावा प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हुआ है।

सो विपक्ष के लिए चुनाव नतीजों के बाद इस

यहीं आकर जनता परिवार और समाजवादी आधार की याद आती है। यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस भी खुलकर उस आर्थिक नीति के परिणाम देखकर विकल्प की बात करने लगी है जिसे लाने में उसकी सरकारों की भी भूमिका है। ये नीतियां दलित, आदिवासी, गाँव और महिला विरोधी हैं यह जाहिर हो चुका है

सवाल को उठाना उचित होगा और अभी सारा ध्यान मोदी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन और लोगों की तकलीफों को उठाने का होना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, संघ के दर्शन का महिला, दलित और पिछड़ा विरोधी होना, सरकारी नीतियों पर बाहरी और संघी दबावों का सवाल और मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां होना चाहिए।

और यहीं आकर जनता परिवार और समाजवादी आधार की याद आती है। यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस भी खुलकर उस आर्थिक नीति के परिणाम देखकर विकल्प की बात करने लगी है जिसे लाने में उसकी सरकारों की भी भूमिका है। ये नीतियां दलित, आदिवासी, गाँव और महिला विरोधी हैं यह जाहिर हो चुका है। नई की जगह पुरानी पेंशन योजना सिर्फ वोट की बात नहीं है, सरकार की जवाबदेही और लोगों को बाजार के हवाले करने की चीज है।

किसान कानून सारी खेती को बाजार के हवाले करने की तैयारी से लाए गए थे। श्रम कानून मजदूरों के अब तक के अधिकारों पर पानी फेरने की तैयारी है। फौज में भर्ती का तरीका सिर्फ सरकारी खर्च बचाने और अपनी जिम्मेवारी से भागने का प्रमाण है। सारी परिवहन और शिक्षा नीति ही चालीस फीसदी कमीशन के लिए चल रही है सिर्फ कर्नाटक की सरकार चालीस फीसदी की न थी।

हवाई यातायात निजी क्षेत्र को सौंपा जा चुका है अब रेल और सड़क परिवहन भी जाने की स्थिति में हैं। अडानी-अंबानी सिर्फ मोदी के दोस्त नहीं हैं यह भविष्य के भारत की झांकी पेश करते हैं। इसलिए इन सवालों को समेट कर जब कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेगा तो खुद को विपक्ष का उम्मीदवार तथा मोदी का विकल्प बताने वाले सारे चेहरे खुद ब खुद बाहर हों जाएंगे।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

राष्ट्रीय फलक पर छा रहे अखिलेश

बुलेटिन ब्यूरो

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिली है। भाजपा की हार के बाद राष्ट्रीय राजनीति में यह बात मजबूती से चल पड़ी है कि भाजपा को परास्त करने के लिए विपक्षी एका की जरूरत है। क्षेत्रीय क्षत्रपों को आगे करने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की

हिमायत को कर्नाटक के नतीजों ने बल दिया है।

लंबे समय से श्री अखिलेश यादव यह बात कहते-करते रहे हैं। उन्होंने इसके लिए न सिर्फ पहल की बल्कि उसके लिए मजबूत माहौल भी तैयार किया। भाजपा की घेराबंदी करने की उनकी पहल को भी अब कर्नाटक में भाजपा की हार से जोड़कर देखा जा रहा है।

कर्नाटक के नतीजा आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया यही दी कि जहां-जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, भाजपा उनका मुकाबला नहीं कर सकती है इसलिए क्षेत्रीय दलों को ही भाजपा के खिलाफ आगे करना होगा। कांग्रेस को उन राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों का समर्थन करना चाहिए। नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला-युवा विरोधी, सामाजिक-बंटवारे, झूठे प्रचारवाली, व्यक्तिवादी राजनीति का 'अंतकाल' शुरू हो गया है।

श्री अखिलेश यादव का यह बयान राष्ट्रीय राजनीति के लिए काफी सकारात्मक और दूरदर्शी माना गया है। हाल के दिनों में श्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय फलक पर काफी अहमियत दी जा रही है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अपनी सकारात्मक सोच, भाजपा से लड़ने की कूवत और युवाओं, समाज के सभी वर्गों का साथ होने की वजह से वह राष्ट्रीय फलक पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में कर्नाटक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय

अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का जिस तरह स्वागत किया गया, वह भी राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते दखल को रेखांकित करने वाला है।

बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में श्री अखिलेश यादव के दौरे के दौरान भी जिस तरह उनका स्वागत-सत्कार हुआ था, तभी यह संकेत मिल गए थे कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने लखनऊ पहुंचकर श्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनके बढ़ते कद पर मुहर लगा दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने पंजाब पहुंचकर श्री अखिलेश यादव ने अपनी संवेदनशीलता का भी एहसास कराया और यह संदेश दिया कि वह नेताजी के पदचिन्हों पर चलने वाले ही हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी का दखल पहले से ही रहा है और भाजपा से मुकाबला करने की उसकी कूवत का देश का हर तबका लोहा मानता रहा है। हाल के दिनों में भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का मुखर होना, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज और जनता का व्यापक समर्थन संकेत है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव अहम भूमिका में नजर आएंगे।

निराश किसानों को अखिलेश से आस

बुलेटिन ब्यूरो

आगरा में थीम पार्क व लैंड पार्सल योजना के तहत किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न मिलने से किसान परेशान हैं। यूपी सरकार से हताश-निराश हो चुके किसानों को अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से आस है। किसानों ने श्री अखिलेश यादव से न्याय दिलाने के लिए मदद करने की गुहार लगाई है। किसान आगरा से लखनऊ खासतौर पर श्री अखिलेश यादव से मदद मांगने पहुंचे थे।

22 मई को किसानों का दल आगरा से लखनऊ पहुंचा। दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मुलाकात की इच्छा जताई। जब यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता चली तो उन्होंने ससम्मान किसानों को बुलाया और उनके बीच आकर इत्मीनान से उनकी बात सुनी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि जो भी संभव होगा, वह और समाजवादी पार्टी किसानों की मदद करेंगे। किसानों ने भी कहा कि वे जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव हमेशा किसानों-गरीबों की मदद करते रहे है और इसीलिए वे भरोसे के साथ आए हैं कि उन्हें अन्याय से बचाया जाएगा। किसानों ने एक ज्ञापन श्री अखिलेश यादव को सौंपा।

किसानों का यह जत्था जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के मौजा रायपुर और रहनकला के किसानों का था। उन्होंने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2009 में आगरा की तहसील एत्मादपुर के मौजा रायपुर एवं रहनकला की 938.75 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण थीम पार्क और लैंड पार्सल योजना के अन्तर्गत किया था। इसका मुआवजा देने में प्रशासन मनमानी कर रहा है। सभी ग्रामीणों में विरोध है।

ज्ञापन में किसानों ने बताया है कि अवशेष 442.12 हेक्टेयर के प्रतिकर का भुगतान कराने के लिए मंडल आयुक्त, आगरा जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण को कई बार धरना देकर तथा पत्राचार से अवगत कराते रहे किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ।

बाद में नई दर तय की गई। किसान इससे असंतुष्ट हैं और 2014 के रेट से मुआवजा मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन सन् 2014 के रेट और अब तक नियमानुसार ब्याज मिलने पर ही देगें। किसानो के नाम खतौनी से कट जाने से वे सरकारी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, केकेसी के लाभ से वंचित हो गए हैं।

किसानों के प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री प्रदीप शर्मा, रामवीर, सुरेन्द्र कुमार, जगदीश यादव, रामनिवास आदि समेत दर्जनों पीड़ित महिलाएं भी शामिल थीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से किसानों की मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी उपस्थित थे।

कृषक आरक्षण चाहते थे चौधरी चरण सिंह

मधुकर त्रिवेदी
वरिष्ठ पत्रकार

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों और पिछड़ों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता। रहन-सहन में वे पूरी तरह गंवई लगते थे। खेती-किसानी और गांव-गरीब से उनका गहरा जुड़ाव था। स्वामी दयानंद के आर्यसमाज और गांधी जी का उनके जीवन पर काफी असर था। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे।

वे हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी धारा प्रवाह लिखते-बोलते थे और तमाम विषयों पर उनकी अध्ययनशीलता से लोग चमत्कृत हो जाते थे। पिछड़ों में सत्ता की भागीदारी की भावना पैदा करके चौधरी साहब ने ऐसी पहल की जिसकी आज भी कोई राजनैतिक दल उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उन्होंने पिछड़े वर्ग के चार कैबिनेट मंत्री बनाए थे।

23 दिसंबर, 1902 को मेरठ कमिश्नरी की हापुड़ तहसील में बाबूगढ़ छावनी के निकट, नूरपुर गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने गांव के परिवेश में पलते-बढ़ते हुए गांव की जिंदगी की तकलीफों और खेती की समस्याओं को बहुत करीब से देखा था। अन्नदाता किसान पर जमींदारों के जुल्म और बिचौलिए-आढ़तियों के शोषण से उनका निकट परिचय था। इन सबका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सत्ता में आने पर भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। 29 मई 1987 को अंतिम सांस लेने तक उनकी चिंता में किसान ही था।

समाजवादी नेता, विचारक मधु लिमये के अनुसार चौधरी चरण सिंह जमीन के स्वामित्व के मामले में व्यापक असमानता के खिलाफ थे और एक किस्म के कृषि-प्रजातंत्र के पक्षधर थे। औद्योगिक क्षेत्र में वह एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में रहे, जिसमें बड़े पैमाने पर तकनीक का प्रयोग सिर्फ उन क्षेत्रों में सीमित हो, जहां उसकी निहायत जरूरत हो। वे गांधी जी की तरह यह भी मानते थे कि

भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। गांवों से उनका आशय लघु और कुटीर उद्योगों से था तो खेत उनके लिए कृषि व्यवस्था के प्रतीक थे।

चौधरी चरण सिंह मानते थे कि गांवों के विकास के लिए प्रशासन तंत्र पर गांव वालों का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि शहरी वर्गों से आए देश के नेतृत्व को देश की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता की परिस्थितियों की न तो सही अनुभूति होती है और न ही उनमें संवेदनशीलता पाई जाती है। ग्रामीण या किसान की समस्याओं को वही अधिकारी या व्यक्ति हल कर सकता है जिसकी सोच किसान जैसी हो।

वे व्यक्ति जो वास्तव में खेती के काम में लगे हैं, वे चाहे भूमि के मालिक हों अथवा काश्तकार, उन लोगों से अलग हैं जो या तो श्रमिक हैं या पूरी तरह अथवा सिद्धांत रूप में जमीन के लगाव से जीविका कमाते हैं, ये काश्तकार या जमीन के मालिक ही हमारे प्रदेश की बड़ी जनसंख्या का भाग हैं इसलिए यथार्थ में खेती में लगे वर्ग को जनता कहा जा सकता है।

चौधरी साहब का मानना था कि खेती एक विशेष प्रकार का नागरिक दिमाग, एक विशेष सम्मान तथा जीवन को एक विशेष दिशा देती है जो औद्योगिक व्यवस्था द्वारा उत्पन्न स्थितियों से भिन्न होती हैं। यही कारण है कि किसान वर्ग से भरे हुए देश में उस व्यक्ति जिसने किसान जीवन के दुखद अनुभवों को भोगा है और जिसे देहाती क्षेत्र के वातावरण का अनुभव प्राप्त है, उसे किसानों के उद्देश्यों तथा ग्रामीण जीवन के अभावों का ज्ञान होता है। गैर कृषि क्षेत्र के लोग किसानों की दुर्दशा को देखने वाली आंख नहीं रखते।

चौधरी साहब का सुझाव था कि एक लोकप्रिय सरकार को यह शोभा देता है कि वह केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे, जो उसकी आकांक्षाओं तथा अभिलाषाओं को निष्ठापूर्वक जनता तक पहुंचा दे। तात्पर्य यह कि कृषि प्रधान देश में ग्रामीण जीवन में अभिरुचि सरकारी सेवा में चयन की एक शर्त होनी चाहिए। जिनका संबंध देहात से है और जो आज भी अपना सम्पर्क गांव से बनाए हुए हैं सेवा चयन में उन्हें ही लिया जाना चाहिए।

किसानों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग के औचित्य पर चौधरी साहब का कहना था कि सार्वजनिक सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों से आए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर न केवल राज्य का प्रशासन जनोन्मुख होगा अपितु उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। यह न तो लाभकर होगा, न सामाजिक और न ही न्यायोचित कि सरकारी प्रशासन पर गैर कृषक समुदाय के सदस्यों तथा लोगों का एकाधिकार हो। विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पेशे वाले समूहों के दावों को समानता तथा बराबरी की कसौटी के आधार पर संगत बनाना होगा अन्यथा इनमें कटुता बनी रहेगी।

सरकारी सेवाओं में किसान को 75 प्रतिशत आरक्षण की दलील देते हुए चौधरी साहब ने देहात तथा किसान समाज को वंचित रखने को एक बहुत बड़ा अपराध कहा है। उनका कहना था कि सार्वजनिक सेवाएं जन-समाज के लागों व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान तो करती ही हैं, साथ ही ये राजनैतिक शक्ति तथा प्रभुत्व के अस्त्र भी बनती हैं। प्रशासन तंत्र नगर निवासियों तथा गैर कृषक समाज के लिए एक किला एवं सुरक्षित स्थान नहीं है और जीवन की अन्य अच्छी चीजें तथा शिक्षा केवल कुछ लोगों के एकाधिकार का क्षेत्र नहीं है बल्कि वह जमीन से पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति की मिली-जुली विरासत है।

अखिलेश सरकार के कामकाज से ब्रिटिश हाईकमीशन प्रभावित

बुलेटिन ब्यूरो

ब्रिटिश हाईकमीशन के मिनिस्टर एवं डिप्टी हाई कमिश्नर सुश्री क्रिस्टीना स्काट सीएमजी एवं नवनियुक्त राजनैतिक मसलों की अध्यक्ष सुश्री नटालिया लेह की अगुवाई में हाईकमीशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। सपा कार्यालय में हुई इस मुलाकात में विभिन्न विषयों पर लंबी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में सीनियर पोलिटिकल इकोनामी एडवाइजर भावना विज एवं अध्यक्ष

राजनैतिक एवं द्विपक्षीय मुद्दे श्री रिचर्ड वारलो भी शामिल थे।

सबसे पहले श्री अखिलेश यादव ने ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारियों का लखनऊ में स्वागत करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का विस्तार से जवाब दिया ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने वार्ता के दौरान कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की पराजय और विपक्ष की जीत पर भी बात की तो श्री अखिलेश यादव ने बताया कि इस चुनाव परिणाम का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भाजपा को मजबूत चुनौती दे रही है। भाजपा सत्य से भागती है। भाजपा में वास्तविकता का सामना करने का साहस नहीं है।

उन्होंने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की विकासकार्यों में रुचि नहीं है। भाजपा सरकार की प्रशासनिक अक्षमता के चलते प्रदेश में विद्युत संकट गहरा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। किसान परेशान हैं। व्यापार चौपट है और महंगाई चरम पर है। भाजपा के वायदे के बाद भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है।

श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार के बारे में बताया कि तब प्राथमिकता से विकास कार्यों को कार्यान्वित किया गया था। लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर लखनऊ में गोमतीनगर में एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया है।अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का जयप्रकाश नारायण इन्टरनेशनल सेन्टर (जेपीएनआईसी) का निर्माण हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो रेल चलाई गई। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी पर रिवरफ्रंट बनाया गया। समाजवादियों ने लखनऊ को विश्व में नई पहचान दी। आज आईपीएल और अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की वजह से लखनऊ पूरी दुनिया में जाना जाता है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किसानों और नौजवानों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों का भारी जनसमर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादियों की प्रतिबद्धता हमेशा रही है। समाजवादी सरकार के कामकाज को जान-समझकर और समाजवादी पार्टी व उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की स्पष्ट नीति से ब्रिटिश हाईकमीशन के अधिकारी प्रभावित हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर तारीफ की।

उत्तराखंड में सपा की चुनावी तैयारियां तेज

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तराखंड प्रदेश की जनसमस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा आंदोलन करने का निश्चय किया है। पार्टी की प्रदेश इकाई की हाल में हुई बैठक में तय किया गया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को तेज किया जाए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर सदस्यता अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे।

समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश इकाई ने 30 अप्रैल को हुई बैठक में

प्रदेश की तमाम समस्याओं पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया। परेड ग्राउंड देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शम्भू प्रसाद पोखरियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यता अभियान चलाने, निकाय चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ।

बैठक में राज्य इकाई ने तय किया कि ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने, उत्तराखंड में मंडल आयोग की सिफारिशों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विफल भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान पाया गया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा क्षेत्र की तबादला नीति, विद्युत दर में बढ़ोत्तरी, विद्युत कटौती, बेरोजगारी, बदहाल गंगा के अलावा चारधाम यात्रा में हो रही असुविधाएं चिंता का सबब हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा और उत्तराखंड लोकसेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा आयोग में भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है।

उत्तराखंड इकाई की इस अहम बैठक में पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉ एस.एन. सचान, उपाध्यक्ष सुरेश परिहार एडवोकेट, महासचिव समीर आलम, कोषाध्यक्ष एसके राय, दिलवर रावत, राजेन्द्र पाराशर, चन्द्रशेखर यादव के अलावा सर्वश्री अतुल शर्मा, शुभम गिरि, हेमा बोरा, संजय सिंह, ज्ञान सिंह यादव, हरपाल शर्मा, कुलदीप शर्मा, लव दत्ता, सुमित तिवारी, राजेन्द्र गर्ग, रमेश सिंह बिष्ट, मोहन कांडपाल, आशीष यादव, डॉ कदम सिंह बालियान, शरद पाण्डेय, विजेन्द्र ध्यानी, महिपाल सिंह, कल्पना शर्मा, आशीष कुमार, डॉ जमील, भगवती प्रसाद त्रिकोटी आदि मौजूद रहे।

पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन पर समाजवादी पार्टी ने दुःख जताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं।

श्री अखिलेश यादव ने 27 मई को गोरखपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के तेरहवीं संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की।

गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से छह बार विधायक रहे व उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी ने 90 साल की उम्र में 16 मई को गोरखपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह अपने पीछे पुत्र पूर्व सांसद भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी, पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के सचिव विनय शंकर तिवारी व एक पुत्री छोड़ गए हैं।

हरिशंकर तिवारी के निधन की खबर सुनकर समाजवादी पार्टी की एक शोक सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई जिसमें पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कहा गया कि पूर्व मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव के अत्यंत करीबी थे। पूर्वांचल के जनप्रिय नेता के निधन से राजनीति में भारी रिक्तता आई है।

जफरयाब जिलानी के इंतकाल पर अफसोस

वरिष्ठ अधिवक्ता व आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी के इंतकाल पर समाजवादी पार्टी ने अफसोस का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढ़स बंधाया। श्री यादव ने कहा है कि एक दानिश्मंद इंसान के रूप में उनकी याद हमेशा बनी रहेगी।

लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने 17 मई को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिलानी के इंतकाल की खबर सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर जन्नतनशीं जफरयाब जिलानी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देने के साथ पूर्व महाधिवक्ता को श्रद्धांजलि दी। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी ने शोकसभा आयोजित कर दो मिनट का मौन रखकर जफरयाब जिलानी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

पत्रकार शीतला सिंह के निधन पर शोक जताया

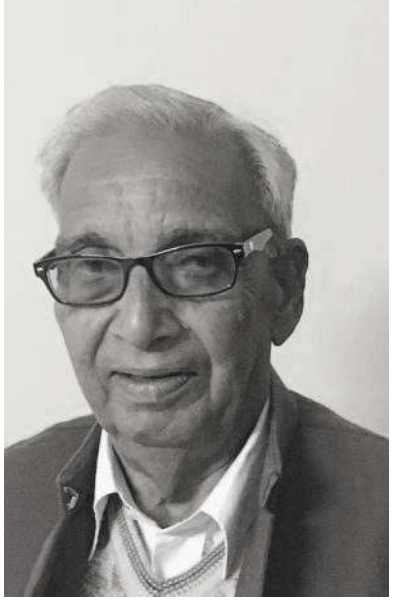

देश के जाने-माने पत्रकार व जनमोर्चा समाचार पत्र के संपादक शीतला सिंह के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने गहरा दुःख जताया है।

एक शोक संदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्री शीतला सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह श्री शीतला सिंह की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में सपा का प्रदर्शन 2017 के मुक़ाबले काफ़ी शानदार रहा। भाजपा ने हर ग़लत तरीक़े से चुनाव को प्रभावित किया फिर भी सपा और अन्य ने मिलकर समेकित रूप से भाजपा से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

उप्र निकाय चुनाव में भाजपा के लगभग 25 सांसदों के क्षेत्र में जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को हराया है। ये महंगाई, बेरोज़गारी, ठप्प कारोबार, ध्वस्त क़ानून-व्यवस्था, नारी-युवा विरोधी भाजपाई सोच व भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनता का फ़ैसला है।

लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा की नाव पलट... twitter.com/i/web/status/1...

Translate Tweet

निकाय चुनाव ने दिए संकेत...सांसदों के लिए आसान नहीं है लोस चुनाव की राह

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 07 May

भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता, महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रबींद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर शत-शत नमन।

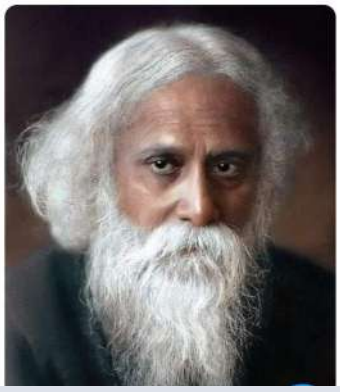

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

नगर निकाय चुनावों में जीते सपा के सभी प्रत्याशियों व भाजपा के ख़िलाफ़ लड़कर जीते सभी 'अन्य' प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई!

नगरों से थोड़ा बाहर आते ही, हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह हारी है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

@ सपा कार्यालय।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

@ सैफई।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला-युवा विरोधी, सामाजिक-बँटवारे, झूठे प्रचारवाली, व्यक्तिवादी राजनीति का 'अंतकाल' शुरू हो गया है।

ये नये सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के ख़िलाफ़ सख़्त जनादेश...

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है... 2000/- के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है लेकिन इसकी सज़ा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है।

शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में श्री @siddaramaiah जी एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में श्री @DKShivakumar जी को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आशा है नया नेतृत्व नये कर्नाटक का निर्माण करेगा।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि।

Translate Tweet

Following

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक-अन्याय का भी।

भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसीलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर ये जनादेश की हत्या है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

भाजपा सरकार ईमानदार अधिकारियों को निष्क्रिय पदों पर भेजकर अपनी बेईमानी का सबूत दे रही है। सहारनपुर में 22 मतों से सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत को दबाव के बाद भी एक सत्यनिष्ठ अधिकारी द्वारा न बदले जाने पर, उसे ही इस सरकार ने बदल दिया।

सपा ईमानदारों अधिकारियों के साथ है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

UPSSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी के 27% की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित किये जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए, भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक़ मारने के ख़िलाफ़ आंदोलन किया जाए। भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

Saddened to hear about the demise of Hinduja Group's chairman Shri Srichand Parmanand Hinduja.

Heartfelt condolences to his family, friends and well-wishers.

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

तालग्राम, कन्नौज।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 11 May

इटावा के वरिष्ठ सपा नेता श्री महावीर सिंह यादव जी का सड़क दुर्घटना में निधन, अत्यंत दुखद!

दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना।

भावभीनी श्रद्धांजलि!

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

लगता है हुक्मरानों ने रहज़नों को दी पनाह है
गुनाहों का दर्ज ना होना भी तो एक गुनाह है!

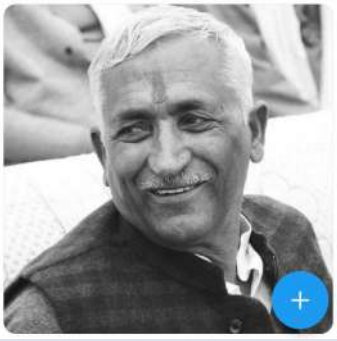

Translate Tweet

शर्मनाक : पुलिस बोल रही थी लूट को दुर्घटना बता दो...

घायल महिला ने अमर उजाला से उजागर की अलीगंज पुलिस की करतूत

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

'इंक़लाब ज़िंदाबाद ' के नारे के साथ हर भारतवासी के मन में आज़ादी की अलख जगाने वाले महान शायर हसरत मोहनी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

कूनो के चीते, आरिफ़ का सारस और इटावा के शेर... भाजपा सरकार में जानवर तक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संकीर्ण राजनीति का शिकार होकर प्रताड़ित किये जा रहे हैं। ये भाजपाई, सत्ता व भ्रष्टाचार छोड़ किसी और से प्यार क्यों नहीं करते?

घृणा प्रेम के दरवाज़े बंद कर देती है।

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh

भावभीनी श्रद्धांजलि।

Translate Tweet

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 48 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

इन्क़लाब का गीत

हमारी ख्वाहिशों का नाम इन्क़लाब है !
हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इन्क़लाब है !
हमारी कोशिशों का एक नाम इन्क़लाब है !
हमारा आज एकमात्र काम इन्क़लाब है !

ख़तम हो लूट किस तरह जवाब इन्क़लाब है !
ख़तम हो भूख किस तरह जवाब इन्कलाब है !
ख़तम हो किस तरह सितम जवाब इन्क़लाब है !
हमारे हर सवाल का जवाब इन्क़लाब है !

सभी पुरानी ताक़तों का नाश इन्क़लाब है !
सभी विनाशकारियों का नाश इन्क़लाब है !
हरेक नवीन सृष्टि का विकास इन्क़लाब है !
विनाश इन्क़लाब है, विकास इन्क़लाब है !

सुनो कि हम दबे हुओं की आह इन्कलाब है,
खुलो कि मुक्ति की खुली निग़ाह इन्क़लाब है,
उठो कि हम गिरे हुओं की राह इन्क़लाब है,
चलो, बढ़े चलो युग प्रवाह इन्क़लाब है ।

हमारी ख्वाहिशों का नाम इन्क़लाब है !
हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इन्क़लाब है !
हमारी कोशिशों का एक नाम इन्क़लाब है !
हमारा आज एकमात्र काम इन्क़लाब है !

- गोरख पाण्डेय
(साभार: कविता कोश)